



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

9 श्रावण 1945 (श10)

(सं0 पटना 634) पटना, सोमवार, 31 जुलाई 2023

सं०-2/आरोप-01-40/2015-6564/सा0प्र0
सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प

6 अप्रैल 2023

श्री अनिल कुमार (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 971/11, तत्कालीन अंचलाधिकारी, बोधगया के विरुद्ध राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 1292 दिनांक 04.11.2015 द्वारा आरोप-पत्र गठित कर उपलब्ध कराया गया।

श्री कुमार के विरुद्ध आरोप है कि :-

“जिला पदाधिकारी, गया के पत्रांक 1902/भू0सु0 दिनांक 10.08.1994 एवं पत्रांक 1636/भू0सु0 दिनांक 30.08.1994 द्वारा कुल-07 फर्जी विदेशी संस्थाओं का निबंधन एवं दाखिल खारिज पर रोक लगाते हुए सृजित जमाबंदी को रद्द करने का आदेश दिया गया था। साथ ही तत्कालीन जिला पदाधिकारी, गया के उक्त निदेश के आलोक में तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, सदर गया के ज्ञापांक 971 दिनांक 15.07.2003 एवं अंचल अधिकारी के ज्ञापांक 479 दिनांक 16.07.2003 द्वारा उक्त जमाबंदी रद्द किया गया।

परंतु उक्त आदेशों के द्वारा फर्जी संस्थाओं के नाम से दाखिल खारिज पर रोक लगाने के बावजूद भी श्री कुमार, तत्कालीन अंचलाधिकारी, बोधगया द्वारा अपने पत्रांक 496 दिनांक 30.11.2007 द्वारा उक्त आदेशों की समीक्षा किए बिना रद्द किये जमाबंदी को पुनः कायम करने का निदेश संबंधित राजस्व कर्मचारी को दिया गया, जिसके आलोक में संबंधित राजस्व कर्मचारी द्वारा पुनः रद्द जमाबंदी को कायम किया गया।”

श्री कुमार के विरुद्ध आरोप एवं इससे संबंधित सम्पूर्ण वस्तुस्थिति के समीक्षोपरांत आरोप की वृहत जाँच हेतु विभागीय संकल्प ज्ञापांक 16736 दिनांक 10.12.2019 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित किया गया, जिसमें आयुक्त, मगध प्रमंडल, गया को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

आयुक्त कार्यालय, मगध प्रमंडल, गया के पत्रांक 1017/विधि दिनांक 13.03.2021 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसमें साक्ष्य के अभाव में आरोपी पदाधिकारी के विरुद्ध आरोप को अप्रमाणित प्रतिवेदित किया गया।

अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन से असहमत होते हुए विभागीय पत्रांक 6888 दिनांक 09.07.2021 द्वारा संचालन पदाधिकारी को अग्रेतर जाँच करने का अनुरोध किया गया। उक्त के आलोक में आयुक्त कार्यालय, मगध प्रमंडल, गया के पत्रांक 1767/विधि दिनांक 09.05.2022 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसमें साक्ष्य के अभाव में आरोपी पदाधिकारी के विरुद्ध आरोप को अप्रमाणित प्रतिवेदित किया गया। जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत जाँच प्रतिवेदन से असहमत होते हुए विभागीय पत्रांक 10591 दिनांक 28.06.2022 द्वारा

श्री कुमार से असहमति के बिन्दु पर लिखित अभ्यावेदन की मांग की गयी। श्री कुमार के पत्रांक 843/आ0प्र0 दिनांक 09.07.2022 द्वारा लिखित अभिकथन समर्पित किया गया।

प्रतिवेदित आरोप, संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन एवं श्री कुमार के लिखित अभिकथन की सम्यक् समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त लिखित अभिकथन को अस्वीकृत करते हुए अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री कुमार के विरुद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम-14 के संगत प्रावधानों के तहत विनिश्चित दंड प्रस्ताव (i) निन्दन (आरोप वर्ष 2017-18) एवं (ii) संचयात्मक प्रभाव से दो वेतनवृद्धि पर रोक का दंड अधिरोपित पर विभागीय पत्रांक 17176 दिनांक 14.12.2022 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से सहमति/ परामर्श की मांग की गई। उक्त के आलोक में आयोग के पत्रांक 3568/लो0से0आ0 दिनांक 14.12.2022 द्वारा श्री कुमार के विरुद्ध विनिश्चित दंड प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त किया गया।

अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार विनिश्चित दंड प्रस्ताव पर बिहार लोक सेवा आयोग से प्राप्त सहमति के आलोक में श्री कुमार के विरुद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14 के संगत प्रावधानों के तहत विभागीय संकल्प ज्ञापांक 23031 दिनांक 21.12.2022 द्वारा (i) निन्दन (आरोप वर्ष 2017-18) एवं (ii) संचयात्मक प्रभाव से दो वेतनवृद्धि पर रोक का दंड अधिरोपित एवं संसूचित किया गया।

उक्त दंडादेश पर विचार हेतु श्री कुमार द्वारा पुनर्विलोकन अभ्यावेदन समर्पित किया गया, जिसमें इनके द्वारा कहा गया है कि संचालन पदाधिकारी द्वारा जमाबंदी को निरस्त करने संबंधी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। विभागीय कार्यवाही को पुनः जाँच हेतु प्रेषित किये जाने से पूर्व उनका पक्ष नहीं लिया गया। साथ ही अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से असहमत होने का कोई पर्याप्त कारण नहीं दिया गया। अंचलाधिकारी से अभिलेख प्राप्त नहीं होने पर उनके विरुद्ध कार्रवाई नहीं की गयी। इसके आलोक में श्री कुमार द्वारा अधिरोपित दंड से मुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

श्री कुमार के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनके पुनर्विलोकन अभ्यावेदन एवं संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की सम्यक् समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि श्री कुमार द्वारा पुनर्विलोकन अभ्यावेदन में उनके ऊपर प्रतिवेदित आरोपों के संदर्भ में कोई तथ्यात्मक बचाव बिन्दु का उल्लेख नहीं किया गया। इनके द्वारा सिर्फ विभागीय कार्यवाही के संचालन में त्रुटि, नियमों को गलत बताने एवं अनुशासनिक प्राधिकार के दायित्वों को ही गलत साबित करने की कोशिश की गयी है। श्री कुमार के अनुसार जिला पदाधिकारी, गया के रूट इन्स्टीट्यूट द्वारा समर्पित आवेदन पर पृष्ठांकित आदेश के आलोक में पुनः जमाबंदी कायम किये जाने के आदेश निर्गत किया गया। जब जिला पदाधिकारी, गया द्वारा रूट इन्स्टीट्यूट द्वारा क्रय किये गये भूमि का रैयती होने के आधार पर जमाबंदी रद्द किये जाने का निर्णय लिया गया था, ऐसे में इस मामले की पूर्ण समीक्षा किये जाने के उपरान्त विधि संगत एवं तथ्यों की पूरी छानबीन के उपरान्त कार्रवाई करने के बाद ही कोई आदेश निर्गत किया जाना चाहिए था। जिला पदाधिकारी, गया के पृष्ठांकित आदेश को आधार बनाकर जमाबंदी आदेश निर्गत करना एक वरीय पदाधिकारी का कर्तव्यों के प्रति लापरवाही दर्शाता है।

श्री कुमार का यह आचरण उनके अनुशासनहीनता, स्वेच्छाचारिता एवं उच्चाधिकारियों के आदेश के प्रति लापरवाही प्रदर्शित करता है। श्री कुमार का यह कृत आचार नियमावली, 1976 के नियम-3(1) के संगत प्रावधानों के प्रतिकूल है।

समीक्षोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री कुमार द्वारा समर्पित पुनर्विलोकन अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए विभागीय संकल्प ज्ञापांक 23031 दिनांक 21.12.2022 द्वारा अधिरोपित दंड को पूर्ववत् बरकरार रखने का निर्णय लिया गया है।

अतएव अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री अनिल कुमार (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 971/11, तत्कालीन अंचलाधिकारी, बोधगया सम्प्रति जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, दरभंगा के विरुद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक 23031 दिनांक 21.12.2022 द्वारा (i) निन्दन (आरोप वर्ष 2017-18) एवं (ii) संचयात्मक प्रभाव से दो वेतनवृद्धि पर रोक का दंड को पूर्ववत् बरकरार रखा जाता है।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधितों को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
शिवमहादेव प्रसाद,
सरकार के अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 634-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>